जनचेतना का प्रगतिशील कथा-मासिक

ISSN 2454-4450

मूल्य ₹ 75

हंस

नवंबर 2025

संपादक
संजय सहाय
•
प्रबंध निदेशक
रचना यादव
•
कार्यकारी संपादक
विवेक मिश्र
•
व्यवस्थापक/सह-संपादन सहयोग
वीना उनियाल
•
संपादन सहयोग
शोभा अक्षर
माने मकर्तच्यान(अवैतनिक)
•
प्रसार एवं लेखा प्रबंधक
हारिस महमूद
•
शब्द-संयोजन एवं रूपांकन
प्रेमचंद गौतम
•
ग्राफिक्स
साद अहमद
•
कार्यालय सहायक
किशन कुमार, दुर्गा प्रसाद
•
मुख्य प्रतिनिधि (उ.प्र.)
राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल
•
रेखाचित्र
मार्टिन जॉन, संदीप राशिनकर, शैलेंद्र सरस्वती, रोहित प्रसाद, आस्था, सिद्धेश्वर

कार्यालय
अक्षर प्रकाशन प्रा. लि.
4229/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2
व्हाट्सऐप : 9717239112, 9560685114
दूरभाष : 011-41050047
ईमेल : editorhans@gmail.com
वेबसाइट :www.hanshindimagazine.in

मूल्य : 75 रुपए प्रति
वार्षिक रजिस्टर्ड : 1250 रुपए (व्यक्तिगत)
संस्था/पुस्तकालय : 1500 रुपए (संस्थागत)
वार्षिक पीडीएफ : 600 रुपए (व्यक्तिगत)
पीडीएफ : 700 रुपए (संस्थागत)
विदेशों में : 80 डॉलर
सारे भुगतान मनीऑर्डर/चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अक्षर प्रकाशन प्रा. लि. (Akshar Prakashan Pvt. Ltd.) के नाम से किए जाएं.

हंस/अक्षर प्रकाशन प्रा.लि. से संबंधित सभी विवादास्पद मामले केवल दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे. अंक में प्रकाशित सामग्री के पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है. हंस में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखकों के अपने हैं. उनसे हंस की सहमति अनिवार्य नहीं है. साथ ही उनके मौलिक या अप्रकाशित होने का उत्तरदायित्व संपादक और प्रकाशक का नहीं है बल्कि यह दायित्व रचनाकार का है.

प्रकाशक/मुद्रक : **रचना यादव खन्ना** द्वारा अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., 4229/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 के लिए प्रकाशित एवं चार दिशाएं, जी-39/40, सेक्टर-3, नोएडा- 201301 (उ.प्र.) से मुद्रित. संपादक–संजय सहाय.

नवंबर, 2025

मूल संस्थापक : **प्रेमचंद : 1930**
पुनर्संस्थापक : **राजेन्द्र यादव : 1986**

पूर्णांक-469 वर्ष : 40 अंक : 4 नवंबर 2025

आवरण : दिनेश खन्ना

जनचेतना का प्रगतिशील कथा-मासिक

इस अंक में

संपादकीय
4. एक शांति पुरस्कार जेनरल पिनोशे के लिए भी! : संजय सहाय

अपना मोर्चा
7. पत्र

मुड़ मुड़ के देख
11. युद्ध : लुइगी पिरांदेलो (अंग्रेजी से अनुवाद : राजेन्द्र यादव) ('हंस', सितंबर 1999)

मुबारक पहला कदम
38. अब भी! : पुष्पेंद्र पाल

कहानियां
14. राजभवन के फूल : जितेन ठाकुर
18. सलूक : गंभीर सिंह पालनी
24. अंतिम शासक : देवेन्द्र चौबे
30. बी पॉजिटिव : संजय कुंदन
36. वह बुद्धिमान है और... : अनामिका अनु
44. अमरबेल : इस्मत चुग़ताई (उर्दू कहानी) (अनुवाद : खुर्शीद आलम)

कविताएं
42. सरस्वती रमेश, चाहत अन्वी, कुँवर रवीन्द्र सिंह
43. अनुराधा ओस, निखिल आनंद गिरि

लेख
50. आलोचना की मुश्किलें : देवेन्द्र चौबे

आधुनिक पाश्चात्य दर्शन और साहित्य
56. आधुनिक साहित्य की विकास यात्रा-5 : अनिल यादव

आराम नगर
60. वर्चस्व और संवैधानिक चेतना की यात्रा : होमबाउंड : गोविंद निषाद

लघुकथा
63. अफसाना-निगार : अशोक कुमार

ग़ज़ल
72. हबीब कैफ़ी 86. अनिल कुमार सिंह

परख
64. समय की नब्ज पकड़ता उपन्यास : अशोक तिवारी
67. स्त्री यातना और मुक्ति का आख्यान : पंकज शर्मा
70. आमजन का कथात्मक रोजनामचा : गोविन्द सेन
73. साहित्यकार की वैचारिक प्रतिबद्धता : महेश दर्पण
76. मानवीय संवेदनाओं का आख्यान : उपमा शर्मा
81. चेतन, अवचेतन और अचेतन का अंतर्गुम्फनः मिथिलेश कुमारी
84. साम्यवादी पूंजीवाद या पूंजीवादी साम्यवाद : विनायक मिश्र

साहित्यनामा
88. मोहि तोहि लागी कैसे छूटै : साधना अग्रवाल

शब्दवेधी/शब्दभेदी
93. प्रसंग सेक्युलरिज्म : तसलीमा नसरीन

रेतघड़ी
96

एक शांति पुरस्कार जेनरल पिनोशे के लिए भी!

जाने-माने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, सोनम वांगचुक 24 सितंबर से जेल में बंद हैं. उन पर सरकार द्वारा नियमों को अनदेखा करते हुए विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के साथ-साथ अनेक आर्थिक अनियमितताओं के और अपने भाषणों से हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं. जब अगस्त 2019 में धारा-370 के विशेष प्रावधानों को हटा दिया गया था तब सोनम वांगचुक सरकार के समर्थन में ज़ोर-शोर से उतर गए थे. उस वक़्त यही सोनम सरकार की आंखों के तारे बने हुए थे. जब से सरकार की वादाख़िलाफ़ी के विरोध में सोनम वांगचुक उठ खड़े हुए हैं, तब से वे उनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं. 2020 के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया था कि वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और छठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे. आज केंद्र-शासित लद्दाख में भाजपा अपने वायदे पूरे करने को तैयार नहीं है. बहुत आसान होता है गुस्से से भरी अवाम में आग का भड़क जाना. जब जनता का मिज़ाज खौल रहा हो तो ऐसी विस्फोटक स्थिति में माचिस की तीली कोई भी बन जा सकता है—फिर चाहे वह भीतर के लोग हों या भेस बदलकर कोई और! ऊपर से अगर सत्ता की शह मिल गई तो कहना ही क्या! फिर तो जलते टायरों, गैस सिलेंडरों से लेकर आरडीएक्स से लदे ट्रक तक बड़ी आसानी से ध्वंस मचाते घूमने लगते हैं. तब कभी भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता, बेशक पांच हज़ार लाशें ही क्यों न गिर जाएं! कुछ लोग बेशर्मी से यह भी कह सकते हैं कि यह सब तो वाकई देशभक्ति और परम त्याग से भरा कृत्य है. ख़ासकर उस देश में जिसे आज़ादी ताज़ा-ताज़ा 2014 में ही प्राप्त हुई हो!

बहरहाल, लेह में घटी दुखद घटना में चार लोगों की मौत की सारी ज़िम्मेदारी भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक के माथे मढ़ दी गई है. देखना है कि सरकार की निरंकुशता जारी रहती है या फिर लोकतंत्र की मर्यादा बचती है.

यूं तो लोकतंत्र के नाम पर दुनिया भर में बड़े बड़े खेल चल रहे हैं. सबसे चमत्कारी बात तो यह हुई है कि लोकतंत्र की सुरक्षा का ठेका उसे जूते की नोक पर रखने वाले ट्रम्प और नेतन्याहू जैसे खलनायकों को सौंप दिया गया है, और इस परम पावन कृत्य को अंजाम देने वाली मारिया कोरिना माचाडो इस वर्ष की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं. हाथ मलते बेचारे ट्रम्प यह सोच सोचकर संतुष्ट हैं कि उन्हें नहीं तो उनकी पालतू को ही सही, नोबेल तो मिला. साथ ही ट्रम्प ने शांति पुरस्कार को भी उसकी हैसियत दिखा दी है.

सात समंदर पार वेनेज़ुएला में एक मुकम्मल तानाशाह और एक नवोदित तानाशाह के बीच सत्ता संघर्ष जारी है. दोनों ही लोकतंत्र के पक्ष में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. लगभग तीन करोड़ की जनसंख्या वाले इस दक्षिणी अमेरिकी ग़रीब मुल्क में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है, जहां किसी भी सत्ताधीश का तानाशाह में बदल जाना चुटकियों का खेल है. संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर इसका और क्या उदाहरण हो सकता है? अपने देश में भी राष्ट्रपति प्रणाली की हिमायत करने वालों को इसका ख़्याल रखना चाहिए. यूं अपने देश की संसदीय प्रणाली ही कब तानाशाहों पर लगाम लगा पाई है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ़ आंखों की शर्म पर ही टिका होता है.

ख़ैर, 1999 में वेनेज़ुएला के क्रांतिकारी नेता और सैन्य अधिकारी उगो चावेज़ एक नए संविधान का प्रस्ताव लेकर जनता के बीच उतरे थे और जनता ने उन्हें बहुमत से चुन लिया. उगो चावेज़ समाजवादी विचारधारा के आधार पर वेनेज़ुएला की राजनीतिक दिशा गढ़ने लगे. वे लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे और उनका मॉडल सबको साथ लेकर चलने वाला था. उनकी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी नीतियां तथा अन्य वामपंथी और समाजवादी सरकारों से उनकी नज़दीकियां, विशेष रूप से फ़िदेल कास्त्रो से उनकी मित्रता भला संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे रास आती! सीआईए का काला खेल आरंभ हो गया. यह वही खेल था जो अनेक मुल्कों के साथ उन्होंने चिले में साल्वाडोर आयेंदे के साथ भी सफलतापूर्वक खेला था. वहां के सैन्य जेनरल अगूस्तो पिनोशे को खरीदकर सीआईए ने न सिर्फ़ आयेंदे की निर्मम हत्या करवा दी थी बल्कि चिले की आत्मा रहे, विश्व के महानतम कवियों में से एक पाब्लो नेरूदा (स्त्रियों को लेकर विवादास्पद) को भी कुछ ही दिनों के भीतर ठिकाने लगा दिया था.

ख़ैर, चावेज़ के पक्षधर थे, तो अनेक विरोधी भी. इन विरोधियों ने सीआईए के षड्यंत्र में शामिल हो, जनता द्वारा चुनी गई सत्ता को समाप्त करने के लिए वेनेज़ुएलन सेना के असंतुष्ट सैनिकों का इस्तेमाल किया और बलपूर्वक तख़्तापलट की कोशिश की, जिसमें 19 लोग हताहत हुए थे और 150 घायल हुए थे. 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाली शांति दूत मारिया माचाडो ने तब इस अमेरिकी षड्यंत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. 2004 में एक बार फिर सीआईए की कठपुतली बन उन्होंने चावेज़ को सत्ताच्युत करने की एक और मुहीम चलाई थी. ऐसा नहीं कि चावेज़ कोई दूध के धुले थे. बाद में तो उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादूरो का कायांतरण पूरी तरह से एक स्वयंभू तानाशाह में हो गया. कभी बस ड्राइवर रहे और फिर ट्रेड यूनियन के रास्ते राजनीति में उतरे मादूरो, चावेज़ के शासन में विदेश मंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति तक की भूमिकाएं निभा चुके हैं. 2013 में उगो चावेज़ की मृत्यु के उपरांत निकोलस मादूरो राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए. मादूरो पर मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गंभीर अपराधों से लेकर चुनावी जालसाज़ियां कर सत्ता से चिपके रहने के अनेक आरोप हैं. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में वेनेज़ुएला 160वें स्थान पर है जबकि 2024 में विश्व गुरु भारत 159वें स्थान पर था. 2025 में अपनी स्थिति को किंचित सुधार 151वें स्थान पर आ टिका है और इतराते हुए वेनेज़ुएला को मुंह बिरा रहा है.

बहरहाल, ग़ौर से देखें तो अमेरिका जैसी एक महाशक्ति वेनेज़ुएला जैसे टुच्चे से देश के ख़िलाफ़ धन-बल-छल से सक्रिय हो जाए तो वहां तानाशाहों का पैदा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है. हालांकि ऐसे शॉर्टकट रास्ते बड़े महंगे साबित होते हैं और अक्सर तानाशाहों को तख़्त से तख़्ते तक उतरने में देर नहीं लगती. अलबत्ता इस पूरी कवायद में जनता की स्थिति बद से बदतर हो जाती है. वह भी तब जब दुनिया के निरंकुश सम्राट बन बैठे श्रीमान ट्रम्प की पालतू माचाडो जैसे लोग अपने मुल्क को गिरवी रखने पर आमादा हों, अमेरिकी एजेंट की तरह काम कर